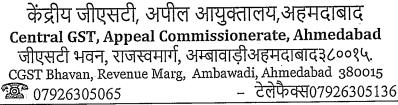


आयुक्त(अपील)का कार्यालय,

Office of the Commissioner (Appeal),





DIN: 20230664SW000000E1F7

स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STP/21/2023 / २०५३ ८ ५० क

अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-50/2023-24 ख दिनाँक Date: 31-05-2023 जारी करने की तारीख Date of Issue 08.06.2023 .

आयुक्त (अपील) द्वारापारित Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals)

- Arising out of OIO No. WS07/O&A/OIO-36/AC-RAG/2022-23 दिनाँक: 29.06.2022 passed by ग Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Ahmedabad South
- अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

Appellant

M/s Bhavesh Rajnikant Patel 101, Samatva Apartment, New Shardamandir Road, Paldi, Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

Revision application to Government of India:

- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को (1) उप–धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a grehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ছা) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/—फीस भूगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/— की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:--Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35—बी/35—इ के अंतर्गत:— Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) उक्तलिखित परिच्छेद २ (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u> की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवनं , असरवा , गिरधरनागर, अहमदाबाद—380004
- (a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor,Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad : 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होत हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

54ण सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण<u>(सिस्टेट)</u>, के प्रतिअपीलो के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

a. (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;

इण लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;

बुए सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया
है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(xxviii) amount determined under Section 11 D;

(xxix) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(xxx) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(XXX) allount payable under reals 5 of the 50 mas of the first किए गए शुल्क के 10% इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती हैं।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of বু আ ন্বা ৩% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where

ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Bhavesh Rajnikant Patel, 101, Samatva Apartment, New Shardamandir Road, Paldi, Ahmedabad (hereinafter referred to as the "appellant") against Order in Original No. WS07/O&A/OIO-36/AC-RAG/2022-23 dated 29.06.2022 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Assistant Commissioner, Division-VII, CGST, Commissionerate: Ahmedabad South [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

- 2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant were not registered with the Service Tax department. They were holding PAN No. AFFPP2413N. The appellant were issued a Show Cause Notice bearing No. V/WS07/O&A/SCN-234/AFFPP2413N/2020-21 dated 23.09.2020 wherein it was proposed to demand and recover service tax amounting to Rs. 5,33,363/- under Section 73 of the Finance Act, 1944 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994. It was also proposed to impose penalty under Section 77(1) and 78 of the Finance Act, 1994. The notice also proposed to impose late fees under Rule 7(c) of the Service Tax Rules, 1994.
- 3. The SCN was adjudicated vide the impugned order wherein the demand of service tax amounting to Rs. 14,510/- was confirmed along with interest. Penalty amounting to Rs. 10,000/- was imposed under Section 77(1)(a) of the Finance Act, 1994. Penalty amounting to Rs. 14,510/- was imposed under 78 of the Finance Act, 1994. Penalty amounting to Rs. 20,000/- was imposed under Section 70 of the Finance Act, 1994 read with Rule 7(c) of the Service Tax Rules, 1994.
- 4. Being aggrieved with the impugned order, the appellant have filed the present appeal contesting the issue on merits. The appellant have also filed an application for condonation of delay wherein it was

bimitted that:

i. The instant appeal was prepared well in time on 11.07.2022. However, at the time of filing it was informed that they need make pre-deposit @ 7.5% of the tax amount. Since they had not obtained service tax registration, they visited the jurisdictional office to obtain provisional registration.

5.

- ii. They generated the Challan but when they tried to make payment, it was indicated that there was no pending Challan. They visited the jurisdictional office several times to resolve the payment issue. However, the same was not resolved.
- iii. By the time the issue got resolved, the appeal got delayed by 58 days. During this period, they visited USA for 2-3 months as their son was studying there.
- iv. The appeal got delayed due to the above reasons. They request that the delay be condoned.
- 5. Personal Hearing in the case was held on 19.04.2023. Shri Dipen Sukhadia, Advocate, appeared on behalf of appellant for the hearing. He reiterated the submissions made in application for condonation of delay in filing appeal.
- 6. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum, the application for condonation of delay and the material available on records.
- 7. It is observed from the records that the present appeal was filed by the appellant on 02.12.2022 against the impugned order dated 29.06.2022, which the appellant claimed to have received on 05.07.2022. It is observed that the Appeals preferred before the Commissioner (Appeals) are governed by the provisions of Section 85 of the Finance Act, 1994. The relevant part of the said section is reproduced below:
 - "(3A) An appeal shall be presented within two months from the date of receipt of the decision or order of such adjudicating authority, made on and after the Finance Bill, 2012 received the assent of the President, relating to service tax, interest or penalty under this Chapter:



Provided that the Commissioner of Central Excise (Appeals) may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of two months, allow it to be presented within a further period of one month."

- 7.1 In the instant case, the impugned order is dated 29.06.2022 and the appellant have admittedly received it on 05.07.2022. Therefore, the period of two months for filing the appeal before the Commissioner (Appeals) ended on 05.09.2022. The further period of one month, which the Commissioner (Appeals) is empowered to allow for filing appeal also ended on 05.10.2022.
- 7.2 In terms of Section 85 of the Finance Act, 1994, an appeal before the Commissioner (Appeals) is to be filed within a period of two months from the receipt of the order being appealed. Further, the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994 allows the Commissioner (Appeals) to condone delay and allow a further period of one month, beyond the two month allowed for filing of appeal in terms of Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.
- 7.3 The appellant was required to file the appeal on or before 05.09.2022 i.e. two months computed from 05.07.2022. Further, the condonable period of one month, in terms of Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994 ended on 05.10.2022. The present appeal filed on 02.12.2022, is, therefore, clearly barred by limitation. Since the appeal in the instant case has been filed beyond this further period of one month, this authority is not empowered to condone delay in filing of appeal beyond the period of one months as per the proviso to Section 85 (3A) of the Finance Act, 1994.
- 7.4 My above view finds support from the judgment of the Hon'ble Tribunal, Ahmedabad in the case of Zenith Rubber Pvt. Ltd. Vs. Commissioner of Central Excise and Service Tax, Ahmedabad 2014 (12) TMI 1215 CESTAT, Ahmedabad. In the said case, the Hon'ble Tribunal

held\that∶

- "5. It is celar from the above provisions of Section 85(3A) of the Finance Act, 1994 that Commissioner (Appeals) is empowered to condone the delay for a further period of one month. The Hon'ble Supreme Court in the case of Singh Enterprises (supra) held that Commissioner (Appeals) has no power to condone the delay beyond the prescribed period. In our considered view, Commissioner (Appeals) rightly rejected the appeal following the statutory provisions of the Act. So, we do not find any reasons to interfere in the impugned order. Accordingly, we reject the appeal filed by the appellant."
- 8. In view of the facts discussed herein above and considering the judgment of the Hon'ble Tribunal, supra, I reject the appeal filed by the appellant on the grounds of limitation.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeal filed by the appellant stand disposed of in above terms.

(Akhilesh Kumar) Commissioner (Appeals)

Date: 31.05.2023

Attested: Nova

(Rekha A. Nair)

Superintendent (Appeals),

CGST, Ahmedabad.

BY RPAD / SPEED POST

To

M/s. Bhavesh Rajnikant Patel, 101, Samatva Apartment, New Shardamandir Road, Paldi. Ahmedabad

The Assistant Commissioner,
Division – VII, CGST,
Commissionerate: Ahmedabad South.



Respondent

Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South.
- 3. The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South. (for uploading the OIA)
- 4. Guard File.
- 5. P.A. File.